भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2335

गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)

कौशल विकास के परिणाम

2335. श्री कपिल सिब्बल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार युवाओं (15-29 वर्ष) के बीच नवीनतम बेरोजगारी दर कितनी है;

(ख) वर्ष 2025 में प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध परिनियोजन दरें क्या हैं; और

(ग) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित रोजगार जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ कौशल विकास पहलों को समन्वित करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि में 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 31.4% से बढ़कर 41.7% हो गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, वर्ष 2015-16 में शुरू की गई पीएमकेवीवाई योजना ने 1.64 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों (31 अक्टूबर 2025 तक) को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

नैसकॉम की अगस्त 2024 में प्रकाशित "एडवांसिंग इंडियाज एआई स्किल्स" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई प्रतिभा के वर्ष 2027 तक 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 6-6.5 लाख पेशेवरों से 12.50 लाख पेशेवरों से भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होने की संभावना है। अब तक, एआई/बिग डेटा एनालिटिक्स प्रौद्योगिकियों के 3.20 लाख अभ्यर्थियों सहित 8.65 लाख अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन/प्रशिक्षण लिया है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "राष्ट्रीय एआई पोर्टल" (https://indiaai.gov.in/) लॉन्च किया है, जो एआई से संबंधित पहलों, अकादमिक अनुसंधान, स्टार्टअप, नीति विकास और थॉट लीडरशिप लेखों के व्यापक भंडारण के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल नैतिक एआई, तकनीकी प्रगति और उद्योग जगत की प्रवृत्तियाँ जैसे विषयों से संबंधित वेबिनार और ऑनलाइन सत्र भी आयोजित करता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 18.56 लाख से अधिक अभ्यर्थी फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पर जुड़े हैं, जिनमें से 3.37 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है।

सरकार युवाओं को उद्योग जगत संबंधी कौशल से लैस करने और उन्हें उभरते तथा नए जमाने की नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के साथ अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग को कार्यान्वित कर रही है।

इसके अलावा, एमईआईटीवाई द्वारा नासकॉम की साझेदारी से कार्यान्वित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत, स्टार्टअप्स को विनिर्माण कंपनियों के उपयोग हेतु एआई आधारित टूल और एप्लिकेशन विकसित करने के लिए सहयोग दिया जाता है। कंपनियों द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में ऐसे कई उपाय प्रयोग में लाए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी), एमईआईटीवाई ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए 'युवाआई: एआई के साथ युवाओं की उन्नति और विकास' नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को समावेशी तरीके से एआई तकनीक और सामाजिक कौशल प्रदान करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को 8 विषयक क्षेत्रों- कृषि, आरोग्य, शिक्षा, पर्यावरण, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्मार्ट सिटी तथा विधि और न्याय में एआई कौशल सीखने और प्रयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****